स्मार्ट समाधान

डॉ. अरविंद सी रानाडे

नवाचार करने की स्वतंत्रता

नवाचार की खोज मानव जाति की एक परिभाषित विशेषता रही है। प्रारंभिक दिनों से जब शिकारी-ग्रामवासियों ने पत्थर के औज़ार बनाए, आग का उपयोग किया और स्थायी कृषि समाज बनाए, तब से मानवता लगातार अपनी रचनात्मकता के माध्यम से दुनिया का आकार बदल रही है। कृषि क्रांतियों ने उन्नत सिंचाई प्रणालियों, फसल चक्रण विधियों और चयनात्मक घरेलूकरण बनाने के तरीकों का विकास किया, जिसने उत्पादकता में काफी वृद्धि की और बाद में शहरीकरण और व्यापार की नींव रखी। इसके अतिरिक्त, लगातार चलने वाली औद्योगिक और तकनीकी क्रांतियों ने मशीनों, वाष्प शक्ति और बड़े पैमाने पर उत्पादन को जन्म दिया, जो अंततः डिजिटल युग, सेवा अर्थव्यवस्थाओं, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अंतरिक्ष अन्वेषण

लेखक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के निदेशक हैं। ईमेलः director@nifindia.org

के क्षेत्रों तक पहुंचे। इस व्यापक मानवीय उन्नति के क्षितिज में विभिन्न समाजों ने अपनी अनूठी भूमिका निभाई है। इनमें भारत का स्थान विशिष्ट है, जहां नवाचार की परंपरा इसकी सभ्यता की आत्मा में गहराई से जड़ी हुई है। पिंगल, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कर जैसे विद्वानों ने गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई। नालंदा, विक्रमशिला, वालभी, पुष्पगिरी जैसे शिक्षा केंद्र एशिया भर से छात्रों और विचारकों को आकर्षित करते हुए वास्तुकला, धातुकर्म, चिकित्सा, आयुर्वेद, भाषाविज्ञान आदि में ज्ञान प्रणाली का पोषण करते रहे। यह ज्ञान सृजन और नवाचार की भावना आज भी भारत में जीवित है, भले ही शताब्दियों से विदेशी आक्रमण, औपनिवेशिक शासन और वैश्विक बाधाओं का सामना करना पड़ा हो, जो इसके बौद्धिक और सांस्कृतिक आधार की गहराई और दृढ़ता का प्रमाण है।

नवाचार की स्वतंत्रता और संवैधानिक भाव

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था और संस्थानों में गहन परिवर्तन कर रहा है, बल्कि स्वतंत्रता के अर्थ में भी एक गहरा रूपांतरण अनुभव कर रहा है। 21वीं सदी में, स्वतंत्रता की परिभाषा केवल राजनीतिक संप्रभुता या औपनिवेशिक शासन की अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस क्षमता से भी जुड़ी है जिसमें कोई व्यक्ति सृजन कर सके, समस्याओं का समाधान कर सके और अपने आसपास की दुनिया को अर्थपूर्ण ढंग से आकार देने में भागीदारी कर सके। इस नए विचार की सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक है 'नवाचार की स्वतंत्रता', जिसे नागरिकों के लिए समाधान निर्माण करने, विकल्प कल्पना करने और स्थानीय ज्ञान को 'ग्लोकल' (वैश्विक+स्थानीय) प्रासंगिकता में बदलने का अवसर, क्षमता और अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता का अभिव्यक्त रूप हमारे अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप्स, इनक्यूबेशन केंद्रों, सतत कृषि करने वाले खेतों आदि में देखा जा सकता है।

हाल ही में, भारत नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से विकेंद्रीकृत कर रहा है, जो मेट्रो शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों तक और स्टार्टअप यूनिकॉर्न से स्व-सहायता समूहों तक विस्तृत है, जिसके परिणामस्वरूप विकास एक वास्तविक स्वतंत्रता बन रहा है। यदि नवाचार लोगों को कार्य करने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, तो नवाचार की स्वतंत्रता संविधान के निर्देशों का स्वाभाविक विस्तार बन जाती है, जैसे कि समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), जीवन और गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद 21), शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए) और वैज्ञानिक सोच और सुधार विकसित करने का कर्तव्य (अनुच्छेद 51ए)।

नवाचार के दायरे को फैलाना

पिछले दशकों में, सरकार ने अनेक पहलों को संस्थागत रूप दिया है जो नवाचार-प्रधान अर्थव्यवस्था बनने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं:

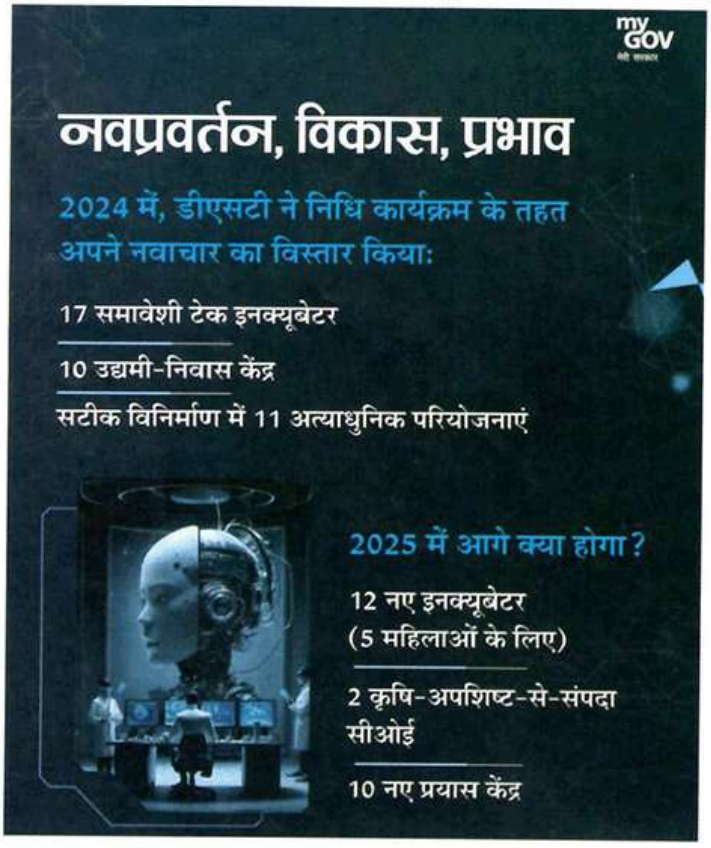

- **रणनीतिक नीतिगत ढांचा और बजटीय प्रयास**

सरकार ने नवाचार-चालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक नीतिगत बदलाव किया है, जो हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025–26 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। सबसे महत्वपूर्ण विकास है रणनीतिक और उभरती तकनीकों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर्स और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए विशेष रूप से 20,000 करोड़ का आवंटन। यह केवल एक सामान्य विज्ञान बजट नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट सरकारी हस्तक्षेप है जो प्रयोग करने की स्वतंत्रता, असफल होने की स्वतंत्रता और व्यावसायिक बनाने की स्वतंत्रता को सक्षम बनाता है। यह फंड हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अधीन जोड़े गए 10,000 करोड़ के डीप-टेक फंड ऑफ़ फंड्स (एफओएफ) के पूरक के रूप में है। डीप-टेक स्टार्टअप्स को लंबी तैयारी अवधि और उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, 10,000 नए प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप की घोषणा की गई है, जिनमें मासिक वजीफ़ा 70,000 से 80,000 रुपये तक है, जिसका उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली मस्तिष्कों को विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान एवं विकास में सम्मिलित करना है। ये उपाय स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सरकार नवाचार को विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अनिवार्यता मानती है।

- **एएनआरएफ का निर्माण और नियामकीय सरलता**

एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार अनुसंधान राष्ट्रीय निधि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना है, जिसे संसद

भारत के लिए AI

नए भारत के लिए नवाचार को बढ़ावा देना

शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में तीन एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे

स्वदेशी आधार पर एआई मॉडल विकसित किए जा रहे हैं जैसे भारतजेन, सर्वम-1, चित्रलेखा और हनुमान का एवरेस्ट 1.0

एआई-संचालित कार्यबल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए उद्योग जगत के अग्रणी के साथ सहयोग

द्वारा 2023 में अधिनियमित किया गया। यह फाउंडेशन पहले के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की जगह लेता है और इसका दायरा काफी व्यापक है। निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास, प्रारंभिक करियर वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय-चालित नवाचारों को सक्षम करने के लिए, एएनआरएफ का उद्देश्य 2023-28 के दौरान 50,000 करोड़ की राशि प्राप्त करना है, जो एएनआरएफ फंड, नवाचार फंड, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान फंड और विशेष प्रयोजन फंड के रूप में होगी। केंद्रीय सरकार द्वारा 14,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान पहले ही किया जा चुका है और शेष राशि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्थाओं, फाउंडेशन और अंतरराष्ट्रीय निकायों से जुटाई जाएगी। इसके अलावा, संस्थानों को वैज्ञानिक उपकरण और अनुसंधान प्रयोजन के लिए उपभोग्य सामग्रियों की खरीदारी में अधिक स्वायत्तता दी गई है, जिससे प्रक्रिया में तेज़ी और देरी कम होगी। इन कदमों के साथ, देश विश्वास आधारित, समावेशी नवाचार शासन के मॉडल की ओर बढ़ रहा है।

हाल ही में, भारत के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 01 जुलाई, 2025 को 1 लाख करोड़ की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है। निजी क्षेत्र द्वारा नवाचार को चलाने और अनुसंधान का व्यावसायीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, आरडीआई योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण प्रदान करना है, जो कम या शून्य ब्याज दरों पर हो। यह योजना निजी क्षेत्र में वित्तपोषण की बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार की गई है और उभरते तथा रणनीतिक क्षेत्रों को विकास एवं जोखिम पूंजी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा देने, तकनीक को अपनाने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का प्रयास करती है। एएनआरएफ इस आरडीआई योजना को व्यापक रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।

- **ज़मीनी स्तर के नवाचार को सशक्त बनाना**

भारत में, अभी भी बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सामाजिक-तकनीकी और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का अभ्यास करते हैं, जैसे कि स्थानीय कृषि तकनीकें, किसान किस्में, पौधा सुरक्षा प्रौद्योगिकियां, मानव और पशु स्वास्थ्य तकनीकें, स्थानीय इंजीनियरिंग समाधान, वस्त्र तकनीकें आदि। ये नवाचार दूरदराज के क्षेत्रों के व्यक्तियों और समुदायों से उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत (एनआईएफ), जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक स्वायत्त संस्था है, लगभग 600 जिलों से खोजे गए ऐसे ज़मीनी तकनीकों और नवाचारों को निरंतर पोषित कर रहा है और उद्योग, अनुसंधान संस्थान, गैर-सरकारी संगठन और विभिन्न स्तरों की सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से उन्हें पूर्ण सहायता चक्र प्रदान कर रहा है। अब तक, एनआईएफ ने ज़मीनी स्तर और छात्र नवाचारकों के लिए 1400 से अधिक पेटेंट दायर किए हैं और 120 से अधिक तकनीकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, जिनमें कई नवाचारकों को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अदृश्यता से मुक्ति का एक रूप है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 'उन्नत भारत अभियान' शैक्षणिक संस्थानों को ग्रामीण भारत से जोड़ता है ताकि उपयुक्त तकनीकों और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से विकासात्मक चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, संस्थान गाँवों के समूह को गोद लेकर उनकी आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और संदर्भानुसार हस्तक्षेप डिज़ाइन करते हैं।

- **नवाचार स्वतंत्रता के प्लेटफॉर्म के रूप में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा**

भारत की नवाचार रणनीति केवल वित्त पोषण और नीतिगत सुधारों तक सीमित नहीं है। सरकार ने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) का निर्माण किया है, जो नए पीढ़ी के उद्यमियों और तकनीकी विकासकर्ताओं के लिए सहायक हैं। उदाहरण के लिए, ओएनडीसी छोटे व्यवसाय मालिकों को अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। 2025 तक, ओएनडीसी ने 7 लाख से अधिक विक्रेता और

सेवा प्रदाताओं को सफलतापूर्वक जोड़ा है, जिनमें से अधिकांश एमएसएमई हैं। इस प्लेटफॉर्म ने मार्च, 2025 तक 20.4 करोड़ से अधिक संचयी लेनदेन भी संसाधित किए हैं, जो नेटवर्क की बढ़ती गति को दर्शाता है। 'स्टेट ऑफ़ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024' के अनुसार, भारत अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए विश्व में तीसरे स्थान पर है। 2030 तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग पांचवा हिस्सा बनने का अनुमान है, जो पारंपरिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही है।

हाल ही में, सरकार ने भारत ऊर्जा स्टैक (आईईएस) भी लॉन्च किया है, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए यूपीआई जैसी एकीकृत, सुरक्षित और इंटरऑपरेबल डिजिटल संरचना बनाने की दूरदर्शी पहल है। यह नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा, डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनी) की दक्षता बढ़ाएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी, भरोसेमंद और भविष्य-तैयार बिजली सेवाएं प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, एक किसान जो सोलर पैनल का उपयोग करता है, वह अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेज सकेगा और सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करेगा। साथ ही, डिस्कॉम स्थानीय बिजली मांग को अधिक सटीकता से ट्रैक कर सकेगा, बिजली चोरी को रोक सकेगा और आपूर्ति अनुसूची या बिजली कटौती के बारे में समय पर उपयोगकर्ताओं को सूचित करेगा। यह डिजिटल प्रणाली विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा पहुंच को अधिक भरोसेमंद, पारदर्शी और समावेशी बनाने की आकांक्षा रखती है, साथ ही भारत के स्वच्छ ऊर्जा और नेट ज़ीरो लक्ष्यों का समर्थन भी करती है।

- **नवाचार का क्षेत्रीय गहनीकरण: स्वास्थ्य, कृषि, एआई और क्वांटम**

क्षेत्र-विशेष मिशन नवाचार-प्रधान रणनीतिक प्रगति को और तीव्र कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत मज़बूती से संस्थागत किया जा रहा है। वर्तमान में 70 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) बनाए जा चुके हैं, 3.49 लाख स्वास्थ्य सुविधाएं हेल्थ सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) पर पंजीकृत हैं, और 5.23 लाख स्वास्थ्य पेशेवर हेल्थकेयर प्रोफ़ेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) पर पंजीकृत हैं। यह डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम कर रहा है, पुनरावृत्ति को कम कर रहा है और नागरिकों को टेलीमेडिसिन, ई-फार्मेसियों और एआई-सहायता प्राप्त डायग्नोस्टिक्स जैसी सेवाओं तक सहज पहुंच प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, 5,000 करोड़ के बजट वाला फ़ार्मास्युटिकल रिसर्च इंसेंटिव प्रोग्राम (पीआरआईपी) भारत को फ़ार्मास्युटिकल और मेडटेक क्षेत्रों में एक वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है।

साथ ही, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान परिषद् (डीएचआर-आईसीएमआर) का 2024-29 कार्य योजना भारत के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को स्वदेशी और सस्ती स्वास्थ्य तकनीकों को बढ़ावा देकर सक्रिय करने का प्रयास करती है। यह प्रतिरोधी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान प्रदान करने, डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को आगे बढ़ाने, अनुसंधान-आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, तकनीकी-संचालित निगरानी को बढ़ाने और चिकित्सा प्रति-उपायों के विकास को तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए काम करती है, जिससे भारत की वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान में स्थिति मज़बूत हो।

इसी समय, कृषि क्षेत्र, जो अभी भी भारत के लगभग 42 प्रतिशत कार्यबल को रोज़गार देता है और राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 18 प्रतिशत योगदान करता है, कृषि 4.0 को अपना रहा है। अगली पीढ़ी की कृषि क्रांति उभरती तकनीकों जैसे ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, कीट पहचान के लिए एआई और मिट्टी और जल प्रबंधन के लिए आईओटी के संयोजन से चिह्नित है। उदाहरण के लिए, ड्रोन दीदी और आकाशदूत पहलें विभिन्न कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं। लक्षित बीज वित्तपोषण, मार्गदर्शन और बाज़ार कड़ियों तक पहुंच के साथ, कृषि-भारत हैकथॉन, युवाओं को कृषि में आकर्षित और बनाए रखने की योजना (एआरवाईए), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई-रफ्तार) और एग्री-टेक इनोवेशन हब जैसे कार्यक्रम कई एग्री-स्टार्टअप्स को पोषित कर रहे हैं जो एआई संचालित सिंचाई सलाहकार उपकरण, मिट्टी परीक्षण के लिए मोबाइल लैब और रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैविक इनपुट विकसित कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, अटल इनक्यूबेशन केंद्र (एआईसी) और

सामुदायिक नवाचार केंद्र (सीआईसी) टियर II और टियर III क्षेत्रों में बढ़ावा दिए जा रहे हैं। एटीएल योजना के तहत, हज़ारों स्कूलों को 3डी प्रिंटर, रोबोटिक्स किट और विज्ञान उपकरण प्रदान किए गए हैं। ये पहल अंतः विषय साइबर-भौतिक प्रणालियों (एनएम-आईसीपीएस) और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) के तहत व्यापक और समन्वित नवाचार ढांचे का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य भारत को डीप टेक में वैश्विक नेताओं में शामिल करना है। ये मिशन न केवल अग्रिम तकनीकों में नवाचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उन क्षेत्रों में घरेलू क्षमता का निर्माण भी करते हैं जो राष्ट्रीय संप्रभुता और सततता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मापन योग्य वैश्विक प्रभाव

भारत की नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र भी वैश्विक विश्वसनीयता प्राप्त कर रही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में, भारत ने 39वां स्थान प्राप्त किया, जो इसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष नवप्रवर्तक बनाता है। डब्ल्यूआईपीओ (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) वर्ल्ड आईपी फाइलिंग्स रिपोर्ट 2023 में, भारत ने पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया, जिससे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, और दक्षिण कोरिया जैसे अग्रणी देशों के बीच आता है, जो बौद्धिक संपदा गतिविधि के मामले में अग्रणी हैं। इसके अतिरिक्त, नेटवर्क रीडिनेस इंडेक्स (एनआरआई) में भारत की स्थिति 2015 में 89वें स्थान से बढ़कर 2024 में 49वें स्थान पर आ गई है। ये संकेत प्रणालीगत परिपक्वता और नीतिगत समन्वय को दर्शाते हैं। 1.57 लाख से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स, 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स और टियर 2 व टियर 3 शहरों से 51 प्रतिशत तक की मज़बूत स्टार्टअप भागीदारी के साथ, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये सफलताएं पेटेंट क़ानूनों के कड़े प्रवर्तन और नियामक अनिश्चितता के समाप्त होने के साथ आती हैं।

भारत की नवाचार संरचना का विस्तार केवल नीति-निर्माण या संस्थागत विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरे राष्ट्रीय जागरण का अनावरण है, जो सामान्य नागरिकों के बीच आत्मशक्ति के पुनरुत्थान का प्रतीक है, जो आत्मविश्वास और साहस के साथ नवाचार के प्रयास में लगे हैं। यह गांधीजी के 'महासागरीय वृत्तों' की याद दिलाता है, जहां नवाचार–स्वयं-सुदृढ़ परिधीय तरंगों के रूप में–हर प्रयोगशाला, कक्षा, खेत और आदिवासी गाँव से फैलता है और जहां व्यक्ति और समुदाय ऊर्जा सृजन के केन्द्र बन रहे हैं और विश्वास, स्वायत्तता और उद्देश्य के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं। सरकार जन भागीदारी, ज़मीनी स्तर की प्रतिभा और समुदाय-चालित समाधानों के माध्यम से सृजन (रचनात्मक अभिव्यक्ति) को सक्षम बना रही है। यह स्वतंत्रता की नई अभिव्यक्ति रचनात्मकता के स्वराज का प्रतिबिंब है, जहां ग्रामीण-आदिवासी ज़मीनी नवप्रवर्तनकर्ता और इसरो के वैज्ञानिक मिलकर अपने-अपने अनूठे तरीकों से विकासित भारत@2047 के विज़न में योगदान दे रहे हैं। समाज के सभी स्तरों पर नवाचार के अवसर प्रदान करके, भारत केवल नवाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक सभ्यतागत क्रांति को भी पोषित कर रहा है। ❑

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
पुणे	ग्राउंड फ्लोर, कैरियर बिल्डिंग, महादाजी शिंदे, बीएसएनएल, टीई कंपाउंड, क्लब के पास, कैंप	411001	
कोलकाता	8, एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बेसेंट नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरू	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
गुजरात	4-सी, नेप्च्यून टावर, चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खादी एंड विल्लेज इंडस्ट्रीज बोर्ड कॉम्प्लेक्स, पो.-सिल्पुखुरी, चांदमारी	781003	0361-4083136